भारत और ओआरएस का संघ।

बनाम

पी. के. कुट्टप्पन

28 फरवरी, 2007

[डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन और अल्टमास कबीर, जे. जे.]

सेवा कानूनः

पिछला वेतन-डाक विभाग-ई. डी. डी. ए.-पता देने वालों को पत्र नहीं देने के आरोप में खारिज कर दिया गया-न्यायाधिकरण द्वारा 50 प्रतिशत सी वेतन-होल्ड के साथ बहाली, शुल्क बहुत गंभीर प्रकृति के होने के कारण इस प्रभाव से संशोधित किए गए आदेश कि बहाली का आदेश केवल 50 प्रतिशत वापस मजदूरी के भुगतान के संबंध में आदेश के हिस्से को ही प्रभावी किया जाएगा।

डाक विभाग में ईडीडीए, प्रत्यर्थी को पंजीकृत पत्रों और अन्य पत्रों और सूचनाओं को पते पर नहीं पहुँचाने के कई आरोपों में डी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने 50 प्रतिशत वापस वेतन के साथ उनकी बहाली का निर्देश दिया। चूंकि विभाग की रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी, इसलिए उसने वर्तमान अपील दायर की।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारण आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं।इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए आदेश को संशोधित किया जाता है और यह आदेश दिया जाता है कि केवल बहाली के आदेश को प्रभावी बनाया जाएगा और 50 प्रतिशत वापस मजदूरी के भुगतान के संबंध में निर्देश को दरकिनार कर दिया जाएगा।इस

तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी-एफ भारत संघ के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया था, और इसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.1.2005 के आदेश को प्रभावी बनाना चाहिए था, प्रतिवादी उस तारीख से वेतन और अन्य भत्तों के साथ 25.01.2005 से बहाली का हकदार होगा।पैरा 6 और 8]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2007 की सिविल अपील सं. 1122।

2002 (एस) के ओ. पी. संख्या 19374 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 25.1.2005 से।

अपीलार्थियों की ओर से टी. एस. दोआबिया, किरण भारद्वाज और वी. के. वर्मा।

उत्तरदाता के लिए ए. जी. प्रकाश।

न्यायालय का निर्णय डॉ. ए. आर. द्वारा दिया गया था। लक्ष्मणन, जे. 1.देरी को माफ कर दिया गया।

2. अनुमति दी गई।

3. सुना गया Mr.T.S.Doabia, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और Mr.G.Prakash, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।

4.उपरोक्त अपील निर्णय और आदेश dt.25.01 के खिलाफ निर्देशित है।2005 में केरल उच्च न्यायालय ने 2002 के आई. डी. 1 में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए 50 प्रतिशत पिछले भत्तों के साथ बहाली का आदेश दिया।

5. हमारा ध्यान प्रतिवादी डी के खिलाफ बनाए गए आरोपों की ओर आकर्षित किया गया था।आरोप इस प्रकार हैंः- "

अनुच्छेद 1

कि श्री P.K.Kuttappan ईडीडीए परक्कडवु के रूप में काम करते हुए शाखा पोस्टमास्टर को 38 साधारण डाक वस्तुओं को वितरित करने या वापस करने में विफल रहे जो उन्हें 16.3.1996,18.3.1996 और 19.3.1996 पर वितरण के लिए सौंपे गए थे और इस तरह पी एंड टी ईडी एजेंट (आचरण और सेवा) नियम, 1964 के नियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण बनाए रखने में विफल रहे।

अनुच्छेद 2

ई. डी. डी. ए. परक्काडवु के रूप में काम करते हुए श्री <आई. डी. 2 ने बीजापुर के आर. एल. 1075 को Sri.I.M.Thomas, इरिम्पन हाउस, पूवाथुसेरी, परक्काडवु को संबोधित नहीं किया, जिसे उन्हें 4.3.96 और बाद के दिनों में वितरण के लिए सौंपा गया था, लेकिन अंत में 19.3.96 पर झूठी टिप्पणियों के साथ लेख को वापस कर दिया और फिर पी. एंड टी. ई. डी. एजेंट्स (आचरण और सेवा) नियम, 1964 के नियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण बनाए रखने में विफल रहे।

अनुच्छेद 3

कि श्री P.K.Kuttappan ने ईडीडीए परक्काडवु के रूप में काम करते हुए पूवाथुसेरी के आरएल 979 को ओमाना थॉमस सी/ओ को संबोधित नहीं किया था I.M.Thomas, इरिम्पन, पूवथुसरी, परक्कडावु ने उन्हें 9.3.96 और उसके बाद के दिनों में सौंपा, लेकिन 1 9.3.96 पर अंतिम झूठी टिप्पणी के साथ इसे वापस कर दिया और फिर P & T ED एजेंट (आचरण और सेवा) नियम, 1964 के नियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण बनाए रखने में विफल रहे। अनुच्छेद 4 कि श्री P.K.Kuttappan ने ईडीडीए परक्काडावु के रूप में काम करते हुए बॉम्बे जीपीओ के वीपी बी-45241 को श्रीमती ओमाना थॉमस, पूवाथुसेरी, परक्काडावु को संबोधित नहीं किया या

सूचना नहीं दी, जिसे उन्हें 12.3.1996 पर सौंपा गया था, लेकिन अंत में 18.3.96 पर "घर लगातार बंद" झूठी टिप्पणियों के साथ लौट आया और इस प्रकार सी पी एंड टी ईडी एजेंट (आचरण और सेवा) नियम, 1964 के नियम 17 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण बनाए रखने में विफल रहा।

6. हमारी राय में, आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं।हालाँकि, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने मामले पर नरमी से विचार करते हुए 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ बहाली का आदेश दिया।

7. हमारी राय में, प्रतिवादी को, यदि केवल 50 प्रतिशत पिछले वेतन के बिना सेवा में बहाल किया जाना चाहिए था और इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के उक्त भाग में और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, संशोधन की आवश्यकता है।इसलिए हम न्यायाधिकरण द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए आदेश को संशोधित करते हैं और केवल 50 प्रतिशत पिछले वेतन के भुगतान के संबंध में पुनर्स्थापना और निर्देश को हटाने का आदेश देते हैं।प्रतिवादी को आज से एक सप्ताह के भीतर बहाल कर दिया जाएगा।

8. यह भी ध्यान देने योग्य है कि विशेष अनुमति याचिका 23.06.2005 पर दायर की गई थी।इस अदालत ने 29.07.2005 पर केवल देरी की माफी के आवेदन, विशेष अनुमति याचिका और अंतरिम राहत के अनुरोध पर भी नोटिस का आदेश दिया है।इसके बाद, मामले को कई तारीखों के लिए स्थगित कर दिया गया और अपीलार्थी-भारत संघ के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया।ऐसी परिस्थितियों में, भारत संघ को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को प्रभावी बनाना चाहिए था।2005 में।चूंकि कोई रोक नहीं है, इसलिए हमारी राय में प्रतिवादी 25.01.2005 G से बहाली का हकदार होगा और वह उस तारीख से वेतन और अन्य भत्तों का भी हकदार है।

9. अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

10. कोई लागत नहीं।

आर. पी.

अपील का निपटारा किया गया।एच.

भवानी शंकर शर्मा

रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी